Statement

S1. No.	High Court	Vacancies of Judges/Additional Judges as on 1.7.1996
1.	Allahabad	3
2.	Andhra Pradesh	2
3.	Bombay	8
4.	Calcutta	8
5.	Delhi	3
6.	Gauhati	1
7.	Gujarat	2
8.	Himachal Pradesh	-
9.	Jammu & Kashmir	1
10.	Karnataka	3
11.	Kerala	5
12.	Madhya Pradessh	5
13.	Madras	4
14.	Orissa	2
15.	Patna	4
16.	Punjab & Haryana	5
17.	Rajasthan	-
18.	Sikkim	1
	Total	57
II.	Supreme Court	1

Opening of Dclhi-Amritsar and Delhi-Chandigarh air route

295. SHRI BHUPINDER SINGH MANN: Will the Minister of CIVIL AVIATION & TOURISM be pleased to state:

(a) whether Government have any plans to open Delhi-Amritsar and Delhi-Chandigarh air route for a large number of passengers;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF CIVIL AVIATION (SHRI CM. IBRAHIM): (a) and (b) Indian Airlines is already operating flights on the sector Delhi-Amritsar and U.P.Airways on the sector Delhi-Chandigarh

(c) Does not arise.

घाटे में चल रहे एयर इंडिया के वायु-मार्गों की पहचान किया जाना

296. **श्रीमती मालती शर्मा:** क्या नागर विमानन और पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एयर इंडिया को किन-किन वायु-मार्गों पर घाटा हो रहा है;

(ख) इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने एयर इंडिया को इस घाटे से उबारने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्री (श्री सी०एम० इब्राहिम): (क) और (ख) एयर इंडिया को यूरोप, कनाडा, यू०के०, अफ्रीका के प्रचालनों पर तथा यू०एस०ए० और सिंगापुर के लिए भारवाही प्रचालनों पर नये विमान पर ब्याज तथा मूल्यह्रास के कारण व्यय में वृद्धि, बढ़ी हुई प्रतियोगिता के कारण आय में कमी, अवतरण, हैंडलिंग तथा दिक्चालन संबंधी प्रभारों में वृद्धि, रुपए के मूल्य में ह्रास इत्यादि कारणों से घाटा होता आ रहा है।

(ग) और (घ) एयर इंडिया और अधिक यात्रियों को आकृष्ट करने तथा राजस्व में वृद्धि के लिए अपने उत्पाद, छवि तथा समयबद्ध कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए कदम उठा रहा है।

बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र के लिए ऋण मुहैया कराने के संबंध में उपबंध

297. **श्री सोमपाल:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस आशय का कोई उपबंध है जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा अपने ऋणों में से कुछ न्यूनतम प्रतिशत ऋण देश की अर्थव्यवस्था के कुछ प्राथमिकता क्षेत्रों और वर्गों को दिया जाना है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह सच है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अधिकांश बैंकों ने इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान बैंकों ने उक्त प्राथमिकता क्षेत्रों के लिए मद-वार कितनी धनराशि और कितने प्रतिशत ऋण दिये हैं;

(ङ) इन लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) सरकार ने उक्त लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं/उठाने का विचार रखती है?

वित्त मंत्री तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) और (ख) जी, हां। वाणिज्यिक बैंकों द्वारा प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के लिए निर्धारित लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:—

(i) सरकारी क्षेत्र और गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक:

कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम: निवल बैंक ऋण का 40 प्रतिशत

कृषि अग्रिम: निवल बैंक ऋण का 18 प्रतिशत

कमजोर वर्गों को अग्रिम: निवल बैंक ऋण का 10 प्रतिशत

(ii) भारत में परिचालन कर रहे विदेशी बैंक:

कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम: निवल बैंक ऋण का 32%

लघु उद्योगों को अग्रिम: निवल बैंक ऋण का 10%

निर्यात उद्योगों को अग्रिम: निवल बैंक ऋण का 10%

प्राथमिकता क्षेत्र में शामिल किए गए मद नीचे दिए गए हैं:—

1. कृषि
2. लघु उद्योग
3. लघु सड़क और जल परिवहन परिचालक
4. खुदरा व्यापार
5. लघु व्यवसाय
6. व्यावसायिक और स्वरोजगार वाले व्यक्ति
7. अ०ज०/अ०ज०ज० के लिए राज्य प्रायोजित संगठन
8. शिक्षा
9. आवास
10. उपभोग ऋण

(ग) और (घ) जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है, मार्च, 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 के अन्तिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी क्षेत्र, गैर-सरकारी क्षेत्र और विदेशी बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम की बकाया राशि विवरण में दी गई है। (नीचे देखिए)

(ङ) और (च) यद्यपि, निवल बैंक ऋण की प्रतिशतता के अनुक्रम में प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों में निरपेक्ष रूप से वृद्धि हुई है, ये निर्धारित लक्ष्यों से नीचे है। भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि इसका एक कारण विवेकपूर्ण मानदण्डों का लागू किया जाना हो सकता है जिसने बैंकों को अपने ऋण पोर्टफोलियो के प्रति सावधान किया है। प्राथमिकता क्षेत्र को ऋण देने के कार्य की निगरानी आवधिक रूप से ग्रामीण ऋण संबंधी अग्रणी बैंक योजना/सेवा क्षेत्र दृष्टि कोण के अन्तर्गत गठित मंच में और साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा की जाती है। क्रमशः दिसम्बर 1994 और मार्च 1994 के अंत तक निवल बैंक ऋण के 18% का कृषि ऋण लक्ष्य प्राप्त न करने वाले सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र के बैंकों से निवल बैंक ऋण के अधिकतम 1.5 प्रतिशत के अध्यधीन राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) में 2000 करोड़ रुपए का ग्रामीण मूलभूत विकास निधि (आरआईडीएफ) में अंशदान करने के लिए कहा गया है। बैंकों द्वारा आर०आई०डी०एफ० में किए गए अंशदान को प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत उनके अप्रत्यक्ष कृषि ऋण के रूप में माना जाएगा। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से कहा गया कि वे कंशार्सियम आधार पर खादी-ग्रामोद्योग कमीशन को 1,000 करोड़ रुपए ऋण दें जिन्होंने 40 प्रतिशत का लक्ष्य अपने आर आई डी एफ अंशदान को शामिल करने के पश्चात् भी प्राप्त नहीं किया है, इस योजना के अधीन के०वी०आई०सी० को बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों को प्राथमिकता क्षेत्र के अन्तर्गत लघु उद्योग के लिए उनके अप्रत्यक्ष ऋण के रूप में माना जाएगा। इस लक्ष्य या उपलक्ष्य को प्राप्त कर पाने में असफल रहने वाले विदेशी बैंकों को भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के पास कमी वाली राशि जमा करानी पड़ती है।

I

विवरण

मार्च 1994, मार्च 1995 और मार्च 1996 के अंतिम शुक्रवार की स्थिति के अनुसार सरकारी, गैर-सरकारी बैंकों और विदेशी बैंकों के प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम की बकाया राशि

(i) सरकारी क्षेत्र के बैंक (करोड़ रुपए)

	1994 मार्च	1995 मार्च	1996 मार्च (अनंतिम)
(क) कुल प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम	53.197	61,794	66,609
निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	37.75	36.56	37.75
(ख) कुल कृषि अग्रिम	21,204	23,513	26,351
निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	15.05	13.91	14.29
(ग) कमजोर वर्गों को अग्रिम	12,779	13,918	15,579
निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	9.07	8.23	8.45

(ii) गैर-सरकारी क्षेत्र के बैंक (करोड़ रुपए)

	मार्च 1994	मार्च 1995	सितम्बर 1995*
(क) कुल प्राथमिकता क्षेत्र	2,886	4,064	4,202
अग्रिम निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	30.2	30.0	33.0
(ख) कुल कृषि अग्रिम	591	816	885
निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	6.2	6.0	6.9
(ग) कमजोर वर्गों को अग्रिम	300	339	348
निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	3.1	2.5	2.7

विदेशी बैंक

(iii) विदेशी बैंक (करोड़ रुपए)

	मार्च 1994	मार्च 1995	मार्च 1996**
(क) प्राथ० क्षेत्र अग्रिम	3,213	4,055	5,417
निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	35.0	39.0	39.0
(ख) लघु उद्योग अग्रिम	941	1,147	1,519
निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	10.0	11.0	11.0
(ग) निर्यात ऋण	2,396	2,992	4,112
निवल बैंक ऋण की तुलना में प्रतिशत	26.0	28.0	29.0

*नवीनतम उपलब्ध

**अनन्तिम